



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6—जनवरी 12, 2007 (पौष 16, 1928)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6—JANUARY 12, 2007 (PAUSA 16, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं शामिल हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400 005, दिनांक 6 दिसंबर 2006

सं. गैबैपवि. 189/मुमप्र (पी.के.) 2006.--भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हितों में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक की स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45अ, 45बक, 45 ट तथा 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. DFC. 118/DG(SPT)-98 में अंतर्विष्ट निदेशों को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित करता है अर्थात्--

1. पैराग्राफ 2(1) में खंड (i) से पहले निम्नलिखित खंड अंकित किया जाएगा :

(ia) "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" का तात्पर्य उस कंपनी से है जो वित्तीय संस्था है; जिसका प्रधान कारोबार वित्तीय गतिविधियों में सहायक भौतिक परिसंपत्तियों, जैसे आटोमोबाइल, ट्रैक्टरों, लेथ मशीनों, जनरेटर सेटों, मशीनरीयल हैंडिलिंग उपकरणों, स्वचालित एवं सामान्य प्रयोजन की औद्योगिक मशीनों, का निरूपण करना है।

2. पैराग्राफ 2(1) के खंड (ii) को हटाया जाएगा।

3. पैराग्राफ 2(1) के खंड (iv) को हटाया जाएगा।

4. पैराग्राफ 2(1) के खंड (viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ऋण कंपनी" से तात्पर्य है ऐसी कंपनी से जो वित्तीय संस्था है जो अपने खुद के कार्यकलापों के अलावा अन्य किसी कार्यकलाप के लिए ऋण अथवा अग्रिम अथवा अन्य किसी प्रकार से वित्त प्रदान करती है; परंतु इसमें परिसंपत्ति वित्त कंपनी शामिल नहीं है।"

5. पैराग्राफ 2(1) के खंड (xi) में "किराया खरीद वित्त कंपनी अथवा उपकरण पट्टादायी कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. पैराग्राफ 2(3) के खंड (ii) में "किराया खरीद वित्त कंपनी अथवा उपकरण पट्टादायी कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. पैराग्राफ 2(3) के खंड (ii) से जुड़ा नोट हटाया जाएगा।

8. पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ 4 के शीर्षक में "उपकरण पट्टादायी कंपनी(उपकं) अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी (किखविकं)" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी(पविकं)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ 4 की पहली पंक्ति में "उपकरण पट्टादायी कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. पैराग्राफ 4(1) के खंड (i) के परंतुक में "उपकरण पट्टादायी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों के स्थान पर "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

11. पैराग्राफ 4(4)(क) तथा (ख) के उप-शीर्षक में संक्षेपाक्षर "उपदा/किखविकं" को "पविकं" संक्षेपाक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. पैराग्राफ 4(4) के उप पैराग्राफ (क) तथा (ख) में "उपकरण पट्टादायी कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. पैराग्राफ 4(5) के खंड (i) में उप-शीर्षक में "उपदाकं/किखविकं" संक्षेपाक्षर को "पविकं" संक्षेपाक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. पैराग्राफ 4(5) के खंड(ii) में "उपकरण पट्टादायी कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. पैराग्राफ 4(6) में "उपकरण पट्टादायी कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. पैराग्राफ 4(12) के खंड(ii) के उप खंड(क) में "उपकरण पट्टादायी कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. पैराग्राफ 9(2) में " किराया खरीद वित्त कंपनी अथवा उपकरण पट्टादायी कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैबैपवि. 190 /मुमप्र(पी.के.)-2006,

भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. DFC. 119/DG(SPT)-98 में अंतर्विष्ट निदेशों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करता है अर्थात्-

1. पैराग्राफ 1(3) के खंड (ii) के उपखंड (ग) के "किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1(3) के खंड (ii) के उपखंड (घ) को हटाया जाएगा।

3. पैराग्राफ 9डी में "पंजीकरण है" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:

" ऐसे प्रमाणपत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्ति/आय के स्वरूप/पैटर्न का उल्लेख भी होगा जिसके कारण कंपनी परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी या ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने के योग्य हुई।"

4. पैराग्राफ 11 बी(i) में "उपस्कर पट्टा कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. पैराग्राफ 11 बी के तीसरे परंतुक में "उपस्कर पट्टा कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त निदेश के पैराग्राफ 13 में वर्णित छमाही विवरणी(एनबीएस-2) के फार्मेट के भाग झ की मद सं.(ii)(क) में अंकित "उपस्कर पट्टा कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनियाँ" शब्दों को "परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली.110 002, दिनांक 2 जनवरी 2007

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या 1 सी० ए० (7)/99/2006

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 से बिलासपुर में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की बिलासपुर शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बिलासपुर के साथ-साथ बिलासपुर नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :-

1. बिल्हा
2. सीपत

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

संख्या: 1 सी० ए० 7/100/2006

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद् दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 22 दिसम्बर 2006 से नैलोर में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की नैलोर शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नैलोर के साथ-साथ नैलोर नगर की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आर्येंगे :-

1. डामारामाडुगु पी० ओ०
2. गुडुर
3. कावाली
4. कोवुर
5. पोटेमपाडु

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

संख्या : यू.16/53/2002/चि.2/(राज.) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, राज्य चिकित्सा आयुक्त(राज.) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नामअवधिकेन्द्र का नाम

डॉ. ए.के. माथुर

2.1.2007 से 1.1.2008तक

पाली(राजस्थान)

डॉ कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400 005, 6th December 2006

No. DNBS. 189/CGM(PK) 2006.—

The Reserve Bank of India, having satisfied that, in the public interest, and to enable the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 , in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect as follows, namely -

1. In paragraph 2(1), before clause(ii), the following clause shall be inserted:

"(ia) "Asset Finance Company" means any company which is a financial institution carrying on as its principal business the financing of physical assets supporting productive / economic activity, such as automobiles, tractors, lathe machines, generator sets, earth moving and material handling equipments, moving on own power and general purpose industrial machines.

2. Clause (ii) of paragraph 2(1) shall be deleted.
3. Clause (iv) of paragraph 2(1) shall be deleted.
4. The clause (viii) of paragraph 2(1) shall be substituted as under:

"loan company" means any company which is a financial institution carrying on as its principal business the providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own but does not include an Asset Finance Company";

5. In clause (xi) of paragraph 2(1), for the words "a hire purchase finance company or an equipment leasing company", the words "an asset finance company" shall be substituted.

6. In clause (ii) of paragraph 2(3) for the words "a hire purchase finance company or an equipment leasing company", the words "an asset finance company" shall be substituted.

7. The note attached to clause (ii) of paragraph 2(3) shall be deleted.

8. In the heading of sub-paragraph 4 of paragraph 4, for the words "Equipment Leasing Company (ELC), Hire Purchase Finance Company (HPFC)", the words "Asset Finance Company (AFC)" shall be substituted.

9. In the first line of sub-paragraph 4 of paragraph 4, for the words "equipment leasing company or hire purchase finance company", the words "asset finance company" shall be substituted.

10. In the proviso to clause (i) of paragraph 4(1), for the words "an Equipment Leasing or Hire Purchase Finance Company", the words "an Asset Finance Company" shall be substituted.

11. In the sub-heading of paragraph 4(4)(a) and (b), for the abbreviations "EL/HPFC" the abbreviation "AFC" shall be substituted.

12. In sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 4(4) for the words "equipment leasing company or a hire purchase finance company", the words "Asset Finance Company" shall be substituted.
13. In sub-heading of clause (i) of paragraph 4(5), for the abbreviations "ELC/HPFC", the abbreviation, "AFC" shall be substituted.
14. In clause(i) of paragraph 4(5), for the words "equipment leasing company or a hire purchase finance company", the words "Asset Finance Company" shall be substituted.
15. In paragraph 4(6), for the words "equipment leasing company or a hire purchase finance company" the words "Asset Finance Company" shall be substituted.
16. In sub-clause (a) of clause (ii) of paragraph 4(12), for the words "equipment leasing company or a hire purchase finance company" the words "Asset Finance Company" shall be substituted.
17. In paragraph 9(2), for the words "a hire purchase finance company or an equipment leasing company" the words "an Asset Finance Company" shall be substituted.

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager In-Charge

No. DNBS. 190 / CGM(PK)-2006

The Reserve Bank of India, having satisfied that, in the public interest, and to enable the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.119/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect as follows, namely -

1. In sub-clause (c) of clause (ii) of paragraph 1(3), for the words "a hire purchase finance company", the words "Asset Finance Company" shall be substituted.
2. Sub-clause (d) of clause (ii) of paragraph 1(3) shall be deleted.
3. In paragraph 9D, after the words "every year", the following words shall be added:
"Such certificate shall also indicate the asset/income pattern of the NBFC for making it eligible for classification as Asset Finance Company, Investment Company or Loan Company."
4. In paragraph 11B(i) , for the words "equipment leasing company or a hire purchase finance company", the words "Asset Finance Company" shall be substituted.

5. In the third proviso of paragraph 11(B), for the words "equipment leasing company or a hire purchase finance company", the words "Asset Finance Company" shall be substituted.

6. In item (ii) (a) of part I of the format (NBS-2) of the half yearly return, referred to in paragraph 13 of the Directions, for the words "equipment leasing and hire purchase finance companies", the words "Asset Finance Companies" shall be substituted.

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager In-Charge

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 2nd January 2007

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/(99)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Bilaspur with effect from 22nd December, 2006.

The Branch shall be known as Bilaspur Branch of Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Bilaspur City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Bilaspur:

1. Bilha
2. Seepat

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

Dr. ASHOK HALDIA
Secy.

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/(100)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Nellore with effect from 22nd December, 2006.

The Branch shall be known as Nellore Branch of Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Nellore City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Nellore :

1. Damaramadugu P O
2. Gudur
3. Kavali
4. Kovur
5. Pottempadu

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

Dr. ASHOK HALDIA
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 28th December 2006

No.U-16/53/2002/Med.II/(Rajasthan): - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. A.K. Mathur	2.1.2007 to 1.1.2008	PALI(Rajasthan)

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रिणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007